

प्रश्न सं. [क. 1486]

**मध्य प्रदेश शासन**  
**वित्त विभाग**  
**वल्लभ भवन- मंत्रालय-भोपाल**

क्रमांक / एफ.11 / 1 / 2008 / नियम / चार,  
प्रति,

भोपाल, दिनांक 07.11. 2009

शासन के समस्त विभाग,  
अध्यक्ष, राजस्व मंडल, ग्वालियर,  
समस्त संभागीय आयुक्त,  
समस्त विभागाध्यक्ष,  
समस्त जिलाध्यक्ष,  
मध्यप्रदेश ।

विषय:- मध्य प्रदेश राज्य की सिविल सेवा के सदस्यों को सेवा में आगे बढ़ने के निश्चित अवसर उपलब्ध कराये जाने हेतु समयमान वेतन (Time Scale Pay) उपलब्ध कराने बावत ।

संदर्भ- वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ-11/1/2008/नियम/चार दिनांक 24 जनवरी, 2008 एवं समसंख्यक परिपत्र दिनांक 1.4.2008, 4.8.2008 एवं 17.9.2009

-0-

राज्य की सिविल सेवा के सदस्यों को सेवा में आगे बढ़ने के निश्चित अवसर उपलब्ध कराये जाने की दृष्टि से वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ-11/1/2008/नियम/चार दिनांक 24 जनवरी, 2008 द्वारा निर्देश जारी किये गये हैं। वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 11/1/2008/नियम/चार, दिनांक 24 जनवरी, 2008 में चतुर्थ श्रेणी (वर्ग -द) के कर्मचारियों को समयमान वेतन देय नहीं था ।

2/ अतः निर्णय लिया गया है कि चतुर्थ श्रेणी के ऐसे कर्मचारियों को जिनके भर्ती नियमों में सीधी भर्ती से नियुक्ति का प्रावधान है, को भी समयमान वेतन योजना दिनांक 1-4-2006 से लागू की जाये । दिनांक 1-4-2006 से 31-8-2008 तक की अवधि के दौरान पात्रता आने पर निम्न तालिकानुसार समयमान वेतन स्वीकृत किया जाये :-

स. क्र.	प्रारम्भिक वेतनमान	12 वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर प्रथम उच्चतर वेतनमान	24 वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर द्वितीय उच्चतर वेतनमान
1.	2550-55-2660-60-3200	2610-60-3150-65-3540	2750-70-3800-75-4400
2.	2610-60-3150-65-3540	2750-70-3800-75-4400	3050-75-3950-80-4590
3.	2750-70-3800-75-4400	3050-75-3950-80-4590	3500-80-4700-100-5200

दिनांक 1-9-2008 से मध्यप्रदेश वेतन पुनरीक्षण नियम, 2009 में उल्लेखित तत्स्थानी वेतन बैंड एवं ग्रेड पे में वेतन निर्धारण किया जाएगा ।

3/ उपरोक्त कंडिका-2 में दर्शित समयमान वेतन स्वीकृत करने के पूर्व विभागों द्वारा यह भी सुनिश्चित कर लिया जाये कि संबंधित सेवा भर्ती नियमों में इन संवर्गों/पदों हेतु सीधी भर्ती का प्रावधान है ।

4/ दिनांक 1-4-2006 अथवा इसके पश्चात् स्वीकृत समयमान वेतन में दिनांक 31-8-2008 तक एरियर्स की राशि का भुगतान म.प्र. वेतन पुनरीक्षण नियम, 1998 के अंतर्गत प्राप्त वेतन के आधार पर तथा दिनांक 1-9-2008 से म.प्र. वेतन पुनरीक्षण नियम, 2009 के अंतर्गत देय होगा ।

5/ वित्त विभाग के संदर्भित परिपत्र क्रमांक.एफ-11/1/2008/नियम/चार दिनांक 24 जनवरी, 2008, समसंख्यक परिपत्र दिनांक 01 अप्रैल, 2008, 4 अगस्त, 2008 तथा 17 सितम्बर 2009 में निहित प्रावधान यथास्थिति लागू होंगे ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार

  
(मिलिन्द वाईकर)  
उप सचिव

म0प्र0 शासन, वित्त विभाग

प्रतिलिपि:-

- 1- राज्यपाल मध्यप्रदेश के सचिव, राजभवन भोपाल
- 2- प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश, विधानसभा, भोपाल
- 3- निबंधक, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर
- 4- प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री सचिवालय, भोपाल
- 5- सचिव, लोक सेवा आयोग, इंदौर
- 6- सचिव, लोक आयुक्त, मध्यप्रदेश, भोपाल
- 7- निज सचिव / निज सहायक मंत्री/राज्यमंत्री, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल
- 8- मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश, भोपाल
- 9- सचिव राज्य निर्वाचन आयोग, मध्यप्रदेश, भोपाल
- 10- रजिस्ट्रार, मध्यप्रदेश राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरण भोपाल /जबलपुर/इंदौर/ग्वालियर ।
- 11- महाधिवक्ता / उप महाधिवक्ता, मध्यप्रदेश भोपाल / इंदौर/ ग्वालियर ।
- 12- महालेखाकार (लेखा ओर हकदारी / (आडिट)-1/2 मध्यप्रदेश ग्वालियर / भोपाल ।
- 13- अध्यक्ष व्यावसायिक परीक्षा मंडल / माध्यमिक शिक्षा मंडल, मध्यप्रदेश भोपाल ।
- 14- प्रमुख सचिव / सचिव / उप सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, भोपाल
- 15- आयुक्त, जनसम्पर्क संचालनालय, मध्यप्रदेश भोपाल
- 16-नियंत्रक शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल की ओर राजपत्र में प्रकाशन के लिए,
- 17- अवर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग(स्थापना शाखा/अधीक्षण शाखा/अभिलेख/मुख्य लेखाधिकारी) मंत्रालय, भोपाल
- 18- मुख्य सचिव के स्टाफ आफिसर मंत्रालय, भोपाल
- 19- समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन मध्यप्रदेश
- 20- सभी प्राचार्य, लेखा प्रशिक्षण शाला, मध्यप्रदेश
- 21- संयुक्त संचालक, जनसंपर्क प्रकोष्ठ, मंत्रालय, भोपाल
- 22- अध्यक्ष, मध्यप्रदेश राज्य कर्मचारी कल्याण समिति कक्ष-84, मंत्रालय, भोपाल
- 23- अध्यक्ष, शासन के समस्त मान्यता प्राप्त कर्मचारी संगठन / संघों
- 24- सभी कोषालय अधिकारी / उप कोषालय अधिकारी
- 25- गार्ड फाईल

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही के लिये अग्रेषित ।



( डी.के. सक्सैना )

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग